निवेशकों की सुविधा के लिए हिंदी में भी होंगे सरकारी फॉर्म

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ईओडीबी की समीक्षा में सेवाओं के सरलीकरण पर जोर**

अमृत विचार : उत्तर प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए अब विभागीय फॉर्म अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निवेश संबधी कागजी सरकारी औपचारिकताओं को अधिक सरल और द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) स्वरूप में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इससे निवेशकों को प्रक्रिया समझने में आसानी होगी और राज्य में निवेश के अनुभव को बेहतर किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोकभवन में बुधवार को उत्तर प्रदेश में व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को और अधिक सरल एवं निवेशकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की भागीदारी रही, जिसका नेतृत्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव सुश्री मीता राजीवलोचन ने किया। उनके साथ कैबिनेट सचिवालय के अपर सचिव राहुल शर्मा, डीपीआईआईटी और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव मीता राजीव लोचन ने खास सुझाव साझा किए, जिनमें डीआईवाई (डू-इट-योरसेल्फ) वीडियो गाइड्स तैयार करना, विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, एक प्रतिक्रियाशील कॉल सेंटर की स्थापना और समस्याओं की ट्रैकिंग के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना शामिल था।